price have they sold your shares? What was the value per share and at what price have you sold it and what is the increase in value of the shares?

SHRI S. KRISHNA KUMAR: Sir, as I said earlier, the evaluation of the shares etc. is done by the Ministry of Finance in consultation with the public sector financial institutions. The dividend last year was Rs. 9.6 crores. (Interruptions) As regards the BEL to which the main question refers, we have certain information from the Canara Bank which is one of the financial institutions. They have paid Rs. 6.16 crores for 11.8 lakh shares roughly. For the face value of 1.18 crores, the payment has been Rs. 6.16 crores or five-times the face value. It has been sold at five times the face value.

SHRI N. K. P. SALVE: Sir, so far as Bharat Electronics Limited is concerned, it is one of the Defence undertakings which has the reputation of doing very well. So far as it goes, the policy of not expanding the capacity where it is available in the private sector, it is all right for themselves. I have nothing to say. But what I am unable to understand is..

MR. CHAIRMAN: Put your question.

SHRI N. K. P. SALVE: My question is what the reservation is in the Defence Ministry for importing technology because the technology in electronics abroad is going by leaps and bounds and this is one undertaking where if they want to mixmise production and optimist productivity. I am unable to understand how they will do it unless they are going to import technology. There should be no reservation (*Interruptions*)

B part of my question is, so far as the foreign exchange is concerned they have potential to export and earn foreign exchange. So why not import technology, upgrade your technology and go in for exports and modernisation? What reservation do you have ?

SHRI S. KRISHNA KUMAR: Sir, Bharat Electronics Limited is the premier electronics manufacturer in the whole country not only in the defence sector....

MR. CHAIRMAN: Answer his question. ... (*Interruptions*) ...

SHRI S. KRISHNA KUMAR: Not only in the Defence sector; 74 per cent indigenisation has taken place and 26 per cent is still imported.

SHRI N. K. P. SALVE: Sir, I seek your protection... (*Interruptions*)..

MR. CHAIRMAN: He has already praised your performance.

SHRI S. KRISHNA KUMAR: Sir, I have a list of foreign collaborations already entered into by this Company in order to achieve technology upgradation. There is no reservation of technology import whatso ever... (*Interruptions*) ...

MR. CHAIRMAN: He is agreeable with you.

SHRI S. KRISHNA KUMAR: There are major foreign collaborations. I have got a list for defence uses... (*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: You are willing to improve your technology. That is all.

SHRI S. KRISHNA KUMAR: There is no reservation. It depends on the state of the technology that we want.

लघु उद्योगों को कोयले की आपूर्ति

*63. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में लघु उद्योगों को कोयले की आपूर्ति नहीं की जा रही है ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान लघु तथा माध्यम उद्योगों द्वारा राज्यवार कुल कितनी मात्रा में कोयले का उपभोग किया गया और गत दो वर्षों के दौरान इन उद्योगों को कोयले की मांग कितनी थी ; और

(ग) मांग की तुलना में कितनी मात्रा में कोयले की आपूर्ति की गयी ?

कोयला मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एस० बी० नयमेगौड़ा : (क) से (ग) एक विवरण पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) जी, नहीं । लघु उद्योगों को कोयले की आपूर्ति नियमित रूप से की जा रही है।

(ख) और (ग) कोयला कम्पनियों द्वारा कोयले की मांग का मूल्यांकन क्षेत्रवार जैसे विद्युत, सीमेंट, उर्वरक, रेलवे आदि के आधार पर किया जाता है और न कि यह राज्यवार आधार पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त, लघु और अन्य उद्योगों के लिये पृथक रूप में मांग का मूल्यांकन नहीं किया जाता है । किन्तु कोयला कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान गैर-महत्वपूर्ण क्षेत्र के उद्योगों को कोल इण्डिया लि० और सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० द्वारा की गई कोयले की कुल मात्रा में आपूर्ति को नीचे दिया गया है :—

वर्ष	मात्रा (मिलियन टन)
1989–90	34.55
1990–91	39.12
1991–92	38.90 (अनंतिम)

श्री ईश दत्त यादव : मान्यवर, सभापति महोदय, कोयला मंत्री जी ने मेरे मूल प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास नहीं किया, और न तो संतोषजनक इनका कोई उत्तर है।

मान्यवर, मेरे प्रश्न का पार्ट बी है--

what was the total quantum of coal consumed by the small and medium scale industries during the last three years State-wise, and what was the demand of coal of these industries?

लघु और मध्यम उद्योगों को कोयले की सप्लाई के बारे में मेरा प्रश्न था। लगता है कि सरकार को लघु और मध्यम उद्योगों में कोई रुचि नहीं है । इसलिये मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि—

"Further, separate demand is not assessed for small and other industries."

तो इसलिये जो मेरा मूल प्रश्न था, जो मैं जानना चाहता था, मंत्री जी से, उस मूल प्रश्न का उन्होंने उत्तर नहीं दिया। मान्यवर, लघु और मध्यम उद्योग जो हैं, यह देश के पिछड़े और देश के सुदूर क्षेत्रों में रहते हैं, जहां पर बिजली उपलब्ध नहीं होती है और ये उद्योग कोयले से चलते हैं और कोयले की पूरी आपूर्ति न होने के कारण ये उद्योग प्रभावित हो रहे हैं और इसमें से अधिकांश उद्योग बन्द हो रहे हैं और सरकार ने इस ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है । इसके कारण कागज उद्योग , चूड़ी उद्योग, चमड़ा उद्योग, ये छोटे-छोटे उद्योग-धन्धे हैं, जो सुदूर क्षेत्रों में रहते हैं, देहातों में रहते हैं, ये समाप्त हो रहे हैं । जो बेकारी और गरीबी समाप्त करने का एक मात्र साधन है, इसके अलावा कोई दूसरा इस तरह का साधन नहीं है, लघु और मध्यम उद्योगों के अलावा । तो सरकार को इसमें रुचि नहीं लगती है ।

तो मेरा माननीय मंत्री जी से, मान्यवर, आपके माध्यम से यह प्रश्न है कि देश में कोयले से चलने वाले उद्योगों को प्रतिवर्ष कितने कोयले की आवश्यकता है, सरकार कितने की आपूर्ति कर पाती है, ? यदि पूरी आपूर्ति नहीं होती है, तो इसका कारण क्या है और इसे पूरा करने के लिये सरकार की क्या योजना है और कितने समय में सरकार लघु और मध्यम उद्योगों को पर्याप्त कोयले की आपूर्ति कर सकेगी ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRI P. A. SANGMA): Sir, I must concede to the hon.

Member that his question has remained unanswered because unfortunately... *(Interruptions)*...

श्री सभापति : पूरा सुन तो लीजिए।

SHRI P. A. SANGMA: I am considering it. Unfortunately, we don't keep records State-wise and industry-wise. After having gone into this question I have given a direction that from now onwards must be kept State-wise as well as industry-wise. So till that is done, it is very difficult for me to answer this question. What we do now is that the industry is divided into two categories. One is the core sector and another is the non-core sector. The non-core sector includes small scale and medium scale industries. So the figure available is only under these two categories. As far as the non-core sector is concerned, in 1990-91 the demand was 40 million tonnes and the supply we had made was 38.90 million tonnes. So the level of satisfaction was about 95 per cent. These are the figures I have got. Now so far as the total demand of coal in the country is concerned, in 1991-92 it was 235.20 million tonnes and we had been able to supply only 220.50 million tonnes which means roughly 95 per cent overall.

श्री ईश दत्त यादव : माननीय सभापति जी, मुझे प्रसन्नता है और मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरे प्रश्न के बाद इन्होंने अपने विभाग को यह निर्देश दे दिया है कि लघु और मध्यम उद्योगों के कोयले की आपूर्ति का आंकड़ा तैयार किया जायेगा। इसके लिये वह बधाई के पात्र हैं। मान्यवर, कोयला आपूर्ति करने के लिये सरकार ने एक नई नीति निर्धारित की है कि जो मेरी जानकारी है और इस नीति के अनुसार अब कोयला उपभोक्ता को क्वार्टरली एडवांस पेमेंट करना पड़ेगा, कोयल की कम्पनियों को। इसके बाद ही उनको कोयले की आपूर्ति हो सकेगी। इसके लिये लघु और मध्यम उद्योगों के एसोशियेशन ने कोई रिप्रजेन्टेशन किया है सरकार के सामन कि उन्हें कोयले की आपूर्ति पुरानी नीति से ही की जाय, अन्यथा नई नीति से वह कोयला क्रय करने में असमर्थ होंगे, क्योंकि यह उनकी शक्ति से बाहर होगा ? मैं आपक माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हू कि क्या कोयला उपभोक्ता एसोसिएशन की तरफ से सरकार को इस तरह का कोई रिप्रेजन्टेशन मिला है और अगर मिला है, तो इस पर सरकार क्या विचार कर रही है ?

SHRI P. A. SANGMA: Sir, the system of cash-and-carry for power sector was introduced from the 1st of October 1991 mainly because we had arrears to the tune of Rs. 1,800 crores and Coal India was becoming very weak financially. I am very grateful to the firms, State Government and the Electricity Boards because they have been paying in advance. So, we have no problem on that side. As far as the small scale industries are concerned, the system is slightly different because the moment coal allotment is made to them they submit their bills. After the submission of the bills they are required to make payment within 48 hours. The small scale industries have been religiously following it. We have no complaints from them. There is no default of payment by the small scale industries. We are quite satisfied with the financial arrangement. I had a meeting with the Coal Consumers Association in the PHD chamber and we have come to an understanding that the present system will continue. There is no complaint about it.

श्री रजनी रंजन साहू : सभापति महोदय, ईश दत्त भाई ने मंत्री महोदय को धन्यवाद दिया है और मैं उनको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उन्होंने मंत्री महोदय को जगाया है।

श्री सभापति : आप प्रश्न करिये औरों को भी जगाना है। और लोग सवाल करना चाहते हैं।

श्री रजनी रंजन साहू : मंत्री महोदय को मालूम है कि लघु और मध्यम उद्योग कोयले के अभाव से खासकर उत्तर बिहार में बंद पड़ हैं। क्योंकि सरकार की

सुनिश्चित व्यवस्था नहीं है जिसकी व्यवस्था वह करने जा रहे हैं। लेकिन जो कोयला स्थानीय डिपो से खरीदा जाता है, स्थानीय कोयला भंडारों से खरीदा जाता है और जिससे छोटे उद्योग चलते हैं वहां कोयले की जगह पर बड़े-बड़े पत्थर दिये जाते हैं।

श्री सभापति : आपका कहना यह है कि कोयले के बजाय पत्थर न दिये जायें, कोयला ही दिया जाए ?

श्री रजनी रंजन साहू : उससे उद्योगों को क्षति होती है यहां तक कि कोटी-स्थित बिजली घर भी बंद हो गये हैं इस तरह के कोयले की सप्लाई की वजह से।

श्री सभापति : प्रश्न क्या है ?

श्री रजनी रंजन साहू : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जो डिपो से कोयला लघु और मध्यम उद्योग को दिया जायेगा उसमें अच्छे कोयले की सप्लाई खदानों से करायेंगे इसका आश्वासन मंत्री महोदय देंगे ?

MR. CHAIRMAN: He wants an assurance that they get only coal and not stones.

SHRI P. A. SANGMA: Sir, I have already stated that in 1991-92 we have been able to satisfy only up to 95%.

MR. CHAIRMAN: He is talking about the quality of coal supplied by the depots. He says they contain a lot of stones rather than coal.

SHRI P. A. SANGMA: Sir, we do receive complaints about the quality from time to time. I must say that we will conitnue to receive these complaints in future also until and unless we are able to supply to the consumer washed coal or beneficiated coal. Sir, as of now, we don't have enough washeries in our country. We are supplying raw coal to consumers. Sir, some complaints are there. But in future...

MR. CHAIRMAN: You try to improve the situation.

श्री रजनी रंजन साहू : कम से कम

श्री पी०ए० संगमा : करेंगे, करेंगे।

श्रीमती सत्या बहिन : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूं कि सरकार की यह नीति रही है कि जो पिछड़े क्षेत्र हैं, जिनका विकास नहीं हुआ है उसमें एक नीति बनी थी कि जो पिछड़े क्षेत्र हैं उसमें सब्सडी दी जाती है और नये उद्योग लगाये जाते हैं। लेकिन मान्यवर उन उद्योगों को चूंकि कोयले की आपूर्ति पूरी नहीं हो पाती है और उद्योग विभाग द्वारा उन इकाईयों के लिए जो संस्तुति की जाती है तो संस्तुति के आधार पर पूरा कोयला नहीं मिलता है और अविकसित क्षेत्र को विकसित करने का सरकार का जो लक्ष्य होता है तो वह पूरा नहीं हो पाता। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूं कि क्या भविष्य में कोई ऐसी नीति बनायेंगे जिससे उन छोटी-छोटी इकाईयों को कोयले की आपूर्ति हो सके, जिनके स्थापित होने से क्षेत्र का विकास तो होता ही है और बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार भी मिलता है। क्या इस तरह की नीति व बनायेंगे ?

SHRI P. A. SANGMA: Sir, I have already said that on the one hand we are not able to meet hundred per cent...

MR. CHAIRMAN: She is asking whether you will give preference to backward areas in allotments.

SHRI P. A. SANGMA: Sir, preference is given according to the core-sector and non-core-sector. It is not area-wise.

MR. CHAIRMAN: She wants to know whether you will do something for the small scale industries which are coming up in backward areas.

SHRI P. A. SANGMA: Sir, I am coming to that point. On the one hand we are not able to supply enough coal and on the other hand we have got enough stock with us. As on today we have got 47 million

tonnes of stock at the pithead. Therefore, we have decided to release 20 million tonnes of coal to consumers. So, whoever wants to take coal out of the 20 million tonnes is free to do so. (*Interruptions*). I hope that in this way some of the problems of the small scale industries will be settled.

SHRI SUNIL BASU RAY: I want to know from the hon. Minister, what the methods are of assessing the demands of industries. I want to know whether there is any method of producing sufficient quantity of coal which may be required by these industries. I want to know whether the demands of the industries are met because they require a particular quality of coal, a particular grade of coal. If the production is not planned accordingly, the collieries will not be able to supply the particular grade of coal to the particular industry in spite of the fact that 47 million tonnes of stock is with us. Of course, nobody knows when it will be written off. I want to know whether sufficient production planning will be made. I also want that industries should be set up near the coal mine so that the transport cost is reduced.

SHRI P. A. SANGMA: Sir, the demands are assessed by different authorities for different sectors. For example, the demands for the power-sector are assessed by the Central Electricity Authority. On the basis of assessment they place their demand and we supply. As far as the none-core sector and small scale and melium scale industries are concerned, their demand is assessed by the Director of Industry of the respective State Governments. They sponsor it and on the basis of it we supply the coal. There are certain areas where the Coal India Limited also makes certain assessments. So, in various areas various authorities are making the assessment. As far as the production targets are concerned, we have already made provisional targets up to 1996-97, till the end of the Eighth Plan. Demand and supply has been assessed and targets have been fixed.

Bungling in the selection of sponsored TV Programmes

*64. SHRI VITHALBHAI M. PATEL:†
SHRI DHULESHWAR MEENA:

Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether any bungling in the selection of sponsored TV programmes has come to the notice of Government;

(b) what are the serials which were approved by the Selection Committee but did not find place in the list released by the Doordarshan Directorate recently;

(c) the serials which were not approved by the Selection Committee but were listed in the said list released by the Doordarshan Directorate;

(d) whether the panel of Selection Committee is being reconvened to look into the matter afresh; and

(e) whether any enquiry is being conducted in this regard?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (KUMARI GIRIJA VYAS): (a) Yes, Sir.

(a) to (e) Communication of the final results regarding the proposals received under the sponsorship scheme of 1990 has been kept in abeyance as the matter has been referred to the CBI.

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

---

†The Question was actually asked on the floor of the House by Shri Vithalbhai M. Patel.